detected by the Coast Guards during the last few months operating near the Indian coastline overlooking the Arabian Sea;

(b) if so, whether these were captured, and identified as working for Pakistan or any other country; and

(c) what steps are being taken to meet the danger posed by possible reconnoitring activities of certain countries against India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) and (b) A number of dhows engaged in smuggling of gold and silver have been apprehended by Coast Guard ships. Some of these dhows have been found to be fitted with modern commercially available radars, satellite navigation and communication equipment. However, no instance has come to the notice of the Coast Guard where such dhows were found to be engaged in spying activities.

(c) The Coast Guard remain ever vigilant to check and apprehend any vessel engaged in unlawful activities in the Indian territorial waters and the Exclusive Economic Zone.

Decommissioning of Tarapur Atomic Power Plant

1622. SHRl PRAMOD MAHAJAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to decommission Tarapur Atomic Power Plant; and

(b) if so, what are the details in this regard stating the steps taken to protect people from radiation problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): (a) Tarapur Atomic Power Plant will be completing its normally estimated economic life of about 25 years in the year 1994-95. However, having regard to the (health of the plant components the plant could be operated for a longer time.

(b) A committee constituted by the Nuclear Power Corporation has made a preliminary study on decommissioning of Tarapur Atomic Power Plant and have submitted a report. Technological options for decommissioning the plant are available. The spent fuel which contains most of the radioactivity will be removed and taken for safe storage | reprocessing. All radioactive parts will be decontaminated to safe levels. The decommissioning procedures and operations will be subject to review by Atomic Energy Regulatory Board. The entire effort is directed towards ensuring that the safety of people and environment is assured.

Names of recipients of payments in Bofors gun deal

1623. SHRI GHUFRAN AZAM:

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Governnient have failed to disclose the names of the recipients of illegitimate payments in the Bofors gun deal; and

(b) if so, what further steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) and (b) The **CBI** is vigorously pursuing its investigations to identify the recipients of payments in the Bofors Gun deal.

बोफोर्स तोप सौदे की जांच

1624. श्री बलराम सिह् यादव :

श्रीमती कैलाश पति :

श्री सैयद सिब्ते रजी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात यह घोषणा की

थी कि बोफोर्स तोप सौदे में शामिल दलालों के नाम 15 दिन के भीतर उजागर कर दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो यह वक्तव्य किस तारीख को दिया गया था तथा अभी तक नाम घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सत्य है कि पिछले छः महीनों के दौरान कथित सौदे के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिये अधिकारियों के बहुत से दल विदेश भेजे गये ।

(घ) यदि हां, तो इस सब में प्रत्येक दल में कितने अधिकारी विदेश भेजे गये, उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया तथा किन-किन तारीखों को दौरा किया ;

(ङ) भारतीय मुद्रा/विदेशी मुद्रा खर्च का अलग-अलग विवरण देते हुये बतायें कि अधिकारियों के दलों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(च) कथित सौदे की जांच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : : (क) और (ख) प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि बोफोर्स तोप सौदे में देश के कानून के अनुसार जांच होगी ।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है । [देखिये अतारांकित प्रश्न 1490 (क) से (ग)]

(च) यह बताना संभव नहीं है कि यह जांच कब तक पूरी होगी क्योंकि जांच कार्य कई देशों में चल रहा है तथा इसमें कई कानूनी मुद्दे अन्तर्गस्त हैं ।

दिल्ली के स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उपस्कर

1625. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अगस्त, 1990 के "जनसत्ता" में "दिल्ली प्रशासन ने चार हजार छात्रों को सड़क पर ला दिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान कुछ स्कूलों में भिन्न-भिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन पाठ्यक्रमों के लिये आवश्यक उपस्कर मशीनरी और औजार आदि की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था कर ली गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इन पर अलग-अलग कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, अधिकांश स्कूलों में प्रबंध कर दिये गये थे ।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान इन पाठ्यक्रमों पर खर्च की गई राशि निम्नलिखित थी:-

1988-89	21.38 लाख रु०
1989-90	45.00 लाख रु०